देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 269 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...विकास की रफ्तार सुस्त

पेज थ्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 5 दिसंबर 2019

मौसम अधिकतम 22.0° न्यूनतम 10.0°

40850.29

2 पाक में महंगाई के लिए भारत जिम्मेदार

7 विराट कोहली फिर बने नंबर-1 बल्लेबाज

एनआरसी को मिली कैबिनेट की मंजूरी

विपक्ष के तेवर तीखे, सरकार बता रही 370 जैसा ऐतिहासिक कदम

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। एसपीजी बिल के बाद अब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। आज कैबिनेट बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इसे अगले सप्ताह सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल में पड़ोसी मुल्कों से शरण के लिए आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने इसे संविधान की भावना के विपरीत बताते हुए कहा है कि नागरिकों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ विपक्षी दल इस पर कड़ा विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार ने भी इस बिल पर आगे बढ़ने की मंशा जाहिर कर दी

है। मंगलवार को हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि यह बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। यही नहीं उन्होंने इस विधेयक की तुलना आर्टिकल 370 को हटाए जाने से भी की। राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह जब इस विधेयक को पेश करें तो सभी लोग सदन में मौजूद रहें। इस बिल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

इस बीच असम और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर राज्यों में इस बिल के विरोध को रोकने के लिए भी सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है।

हंगामा

■बीजेपी ने सभी सांसदों से की सदन में मौजूद रहने की अपील

राज्यसभा में मिल सकता जेडीयू-अकाली का साथ

सरकार इस बिल को अल्पसंख्यक विरोधी बताए जाने की बात को खारिज कर रही है। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पड़ोसी देशों से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को शरण देना मोदी सरकार की सर्वधर्म समभाव की नीति का परिचायक है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट जैसे दल इस बिल का तीखा विरोध कर रहे हैं और बीजेडी ने भी कुछ ऐतराज जताए हैं। इसके बाद भी बीजेपी के पास लोकसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या है।

कुपवाड़ा और बांदीपोरा में आए हिमस्खलन में 4 जवान शहीद

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में मंगलवार को हुई हिमस्खलन की घटना में 4 जवान शहीद हो गए। मंगलवार को कुपवाड़ा जिले के तंगधर सेक्टर में एक सैन्य कैंप हिमस्खलन की चपेट में आ गया था जिसके बाद कई जवान लापता बताए जा रहे थे। सेना के सूत्रों का कहना है कि इस घटना में भारतीय सेना के तीन जवानों की मौत हो गई। वहीं बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर में आर्मी पट्रोल के बर्फीले तूफान के चपेट में आने से 1 जवान शहीद हो गया।

बता दें कि उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में मंगलवार देर शाम जगह-जगह हिमस्खलन की घटनाएं सामने आईं। कश्मीर के कुपवाड़ा और बांदीपोरा जिलों में हुई हिमस्खलन की अलग-अलग घटनाओं में कई जवान लापता बताए गए। लापता जवानों की तलाश में सेना की एआरटी को लगाया गया था।

18 नवंबर को 4 जवान शहीद हुए: बता दें कि हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में हुई अलग-अलग हिमस्खलन की घटनाओं में कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सियाचिन को दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तीन दिन पहले सियाचिन के दक्षिणी इलाके में हुए हिमस्खलन में सेना के दो जवान शहीद हुए थे। इससे पहले 18 नवंबर को भी सियाचिन ग्लेशियर में हुए भीषण हिमस्खलन में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा दो पोर्टरों की भी मौत हो गई गई थी।

दुखद

मंगलवार को हिमस्खलन की चपेट में आया था भारतीय सेना का कैंप

1984 से अबतक 1000 से अधिक जवान शहीद

सियाचिन में इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसों में भारतीय सेना के सैकड़ों जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, साल 1984 से लेकर अब तक हिमस्खलन की घटनाओं में सेना के 35 ऑफिसर्स समेत 1000 से अधिक जवान सियाचिन में शहीद हो चुके हैं। 2016 में ऐसे ही एक घटना में मद्रास रेजीमेंट के जवान हनुमनथप्पा समेत कुल 10 सैन्यकर्मी बर्फ में दबकर शहीद हो गए थे।

संक्षिप्त समाचार

निर्भया कांड के दोषी की दया याचिका गृह मंत्रालय को मिली

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्भया कांड के एक गुनहगार की दया याचिका मिल चुकी है। मंत्रालय जल्द ही दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजेगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दया याचिका को खारिज किए जाने की सिफारिश की थी। अगर राष्ट्रपति दया याचिका को खारिज कर देते हैं तो निर्भया के गुनहगारों को जल्द फांसी पर लटकाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने निर्भया कांड के एक दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी।

संसद से पास अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक, 2019 बुधवार को पारित हो गया। इसके साथ ही दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आज ऊपरी सदन में इस विधेयक को पेश किया गया जिसपर चर्चा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब विकास के वह सभी लाभ मिल सकेंगे जिनसे अब तक वंचित रहे हैं। चर्चा के बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

सिरामिक फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना में 18 भारतीयों की मौत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) खार्तूम। सूडान में सिरामिक फैक्ट्री में मंगलवार को एलीपीजी टैंकर विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई जिसमें 18 भारतीय हैं। इस घटना में 130 से अधिक लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना की पुष्टि करते हुए आपातकालीन नंबर जारी किया है। वहीं, सूडान में मौजूद दूतावास ने बुधवार को बताया खार्तूम में सीला सिरामिक फैक्ट्री में हुई इस घटना में कई भारतीय गंभीर रूप से घायल भी हैं।

पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)
नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कांग्रेस उत्साह में है। 106 दिनों के बाद चिदंबरम अब रिहा हो सकेंगे। अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफिंग नही करेंगे। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।

कहा जा रहा है कि गुरुवार को वह सुबह 11 बजे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने पी. चिदंबरम को बेल मिलने को सत्य की जीत करार दिया है।

रेलवे की आय 10 साल में सबसे कम

सैलरी और सामाजिक दायित्वों में जा रहा है रेलवे का बड़ा फंडः रेलमंत्री

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे की कमाई 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जिसका मतलब यह है कि रेलवे को 100 रुपये कमाई के लिए 98.44 रुपये खर्च करने पड़े हैं। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए सातवें वेतन आयोग की वजह से सैलरी और पेंशन पर बढ़े खर्च और सामाजिक दायित्वों के बोझ को जिम्मेदार बताया

है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में दिए लिखित जवाब में कहा कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद से रेलवे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 22 हजार करोड़ रुपये अधिक खर्च कर रहा है, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। गोयल ने यह भी कहा कि नई लाइनों के निर्माण और सामाजिक दायित्वों के तहत अलाभकारी इलाकों में भी ट्रेन चलाने में भी इसके फंड का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।

सामाजिक दायित्व और लाभकारी सेक्टर के लिए अलग हो बजटः गोयल ने कहा, जब हम पूरे पिक्चर को देखते हैं, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना और सामाजिक दायित्व के तहत ट्रेनों को चलाने से ऑपरेटिंग रेशियो एक साल में 15 पर्सेंट नीचे चला जाता है। रेलमंत्री ने कहा, समय आ गया है कि हम सामाजिक दायित्वों पर खर्च और लाभकारी सेक्टर्स के लिए बजट को अलग करने की संभावना तलाशें।

खर्च का रेलवे पर असर

प्रश्नकाल में रेलमंत्री ने कहा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर 22 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। ऑपरेटिंग लॉस में इसका योगदान है। मंत्री ने कहा कि रेलवे साफ-सफाई, उपनगरीय ट्रेन चालने और गेज बदलाव पर भी काफी खर्च कर रहा है।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

हमारे सैनिक भी उनकी सीमा में चले जाते हैं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। भारतीय सीमा में अकसर चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर लोकसभा में जवाब देते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भी उधर चले जाते हैं। लोस में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वास्तविक सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच कई जगहों पर भ्रम की स्थिति

■चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर रक्षामंत्री ने दिया बयान

है। कभी-कभी पीएलए इधर आती है और कई बार हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, सीमा सुरक्षा को लेकर मैं पूरे देश को आश्वस्त करता हूं। एलएसी को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ भ्रम हैं। इसके चलते कभी-कभी चीन की पीएलए और भारतीय सेना इधर-उधर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा को लेकर चीन से किसी भी विवाद से निपटने के लिए हमारे पास मेकेनिज्म मौजूद है।

सीमा विवाद पर बातचीत के लिए है जरूरी मेकेनिज्मः उन्होंने कहा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अकसर मीटिंग होती हैं। लॉन्ग टर्म मुद्दों पर भी समाधान के लिए हमारे पास पर्याप्त मेकेनिज्म है।